

गहलोत ने 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन से मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की

प्रदेश में 2600 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल व आरओबी निर्माण की घोषणा

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा विधानसभा में की है। मजदूरों की चिंताओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा विधानसभा में की है। मजदूरों की चिंताओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा विधानसभा में की है। मजदूरों की चिंताओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा विधानसभा में की है।

- जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में 100-100 करोड़ रु. से विकास कार्यों की घोषणा
- तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन करने की भी घोषणा
- जबकि पिछली बजट की घोषणा के 1.35 करोड़ स्मार्टफोन आज तक नहीं बांटे गए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2600 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल व आरओबी निर्माण व अन्य कार्य करवाए जाएंगे। महाकाल उज्जैन की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास किया जाएगा। साथ ही, तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास के लिए पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।

जयपुर में हैरिटेज इलाके में 200 करोड़ की लागत से नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिलों के 8 कस्बों तथा 1473 गांवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश के आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़कों से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स संचालित किए जाएंगे, ताकि

कोरोनाकाल के दौरान हुए शैक्षणिक नुकसान को भरपाई की जा सके। इससे 70 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। साथ ही स्कूली शिक्षा की सुविधा सुलभ करने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय व विषय प्राथम्य किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को 2 सेट निःशुल्क यूजीपीएम उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा साथ ही, 6843 शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैदाउचर्स) भर्ती किए जाएंगे। कार्मिकों को माई 2023 से सेवानिवृत्त के दिन ही समस्त पेंशन परिलालों की स्वीकृति जारी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में मूल वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा।



जयपुर के सीकर रोड पर शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बीच गुजरते वाहन। आसमान में छाए काले बादलों व आंधी-बारिश के कारण शाम को साढ़े 5 बजे ही अंधेरा छाया।

कैदियों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी गठन का आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और जेल में नए वोकेशनल कोर्स शुरू करने के संबंध में सुझाव देने के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कमेटी तीन माह में अपनी सिफारिश राज्य सरकार के समक्ष पेश करे। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश परमेश्वरी देवी की याचिका पर दिए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आधुनिक समय में रोजगार के अवसरों में कंप्यूटर शिक्षा सहित अन्य विशेष शैक्षणिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन्हें लागू करना जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

कोई उपयोग नहीं है। इन कोर्स की जगह पर नर्सिंग और एलएलबी सहित अन्य व्यावसायिक कोर्स कराए जाने चाहिए। याचिका में कहा गया कि बढ़ते कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलीकरण के चलते इन कोर्स को ऑनलाइन कराया जा सकता है। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि

लोकेंद्र सिंह कालवी को श्रद्धांजलि

जयपुर। जी एस फाउंडेशन द्वारा श्री राजपुत्र करणी सेना के शीर्ष संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी की स्मृति में शोटवाड़ा स्थित गणेश मंदिर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्री राजपुत्र करणी सेना, शीर्ष फाउंडेशन, गजेन्द्र सेवा संस्थान सहित कई सामाजिक संगठन पदाधिकारी और अनेक लोग उपस्थित हुए और स्वर्गीय कालवी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

'स्वच्छ भारत मिशन की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही'

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय सोल्लिड वेस्ट एसोसिएशन (आईएसडब्ल्यू) कार्यकारिणी सदस्यों ने सीडीसी ट्रस्ट प्रबंधन की अगुवाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां से उनके जयपुर स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट की। सीडीसी ट्रस्ट प्रबंधन की ओर से ट्रस्ट के सचिव डॉ. विवेक अग्रवाल, सीईओ सिद्धांत अग्रवाल, मुख्य विवा अंधिकारी शिवांगी सुलतानिया, इस्वा उपाध्यक्ष अरुने रेगोशानि, प्रबंध निदेशक मार्क, तेल अवीव (इजरायल) डिप्टी मेयर डोरेन सफिर, निदेशक अदिति रोमला, बोर्ड सदस्य ऐना लोरिया, हो डी लियोग, जेम्स ला, वित्त अधिकारी नैसी स्ट्रैंड उपस्थित रहीं। इस दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट भी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा विभिन्न देशों में टोस कचरा प्रबंधन में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराया जयपुर जिले के आमेर में सेवापुरा लैंडफिल साइट की स्वच्छता के बारे में और इसके रिक्लेमेशन को जल्दी करने के लिए संभव उपायों के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान तेल अवीव के डिप्टी मेयर डोरेन सफिर से एक प्रतिनिधिमंडल अपने यहां भेजने का अनुरोध किया, जिससे वहां किए जा रहे लैंडफिल मैनेजमेंट कार्यों को राजस्थान में भी किया जा सके और भविष्य में यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित की जा सके। अंतरराष्ट्रीय सोल्लिड वेस्ट एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के स्वच्छ

भारत मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। सतीश पूनियां ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि सोल्लिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को भाजपा की सरकार बनने पर 2023 में एक व्यवस्थित ब्लूप्रिंट के साथ कार्ययोजना बनाकर राजस्थान में प्राथमिकता से लागू करेंगे और वेस्ट को वेथेथ में कन्वर्ट करने पर हमारा विशेष ध्यान होगा। उन्होंने कहा कि, भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेशभर के निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए सोल्लिड वेस्ट मैनेजमेंट को

राइट टू हेल्थ बिल को लेकर फिर विवाद गहराया

पलाना नहीं कर रहे हैं। इस वादाखिलाफी के आक्रोशित होकर जॉइंट एक्शन कमेटी ने शनिवार सुबह आठ बजे से चिरंजीवी और आरजीएएस योजना के बहिष्कार को का निर्णय लिया है।

राजस्थान आवास मण्डल, राउत द्वितीय पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराया।

मजबूत किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया जाएगा। इस दौरान संवाद के दौरान सतीश पूनियां ने डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट से सोल्लिड वेस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल बनाने और सेवापुरा कचरा प्रबंधन के निस्तारण को लेकर चर्चा की। सतीश पूनियां ने प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2014 से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर संवाद किया और इसी के साथ राज्य में सुचारु और प्रबंधन की नीति एवं आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने आमेर के सेवापुरा कचरागाह की भयावहता एवं उससे हो

अंतरराष्ट्रीय सोल्लिड वेस्ट एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां से भेंट की।

भारत मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। सतीश पूनियां ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि सोल्लिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को भाजपा की सरकार बनने पर 2023 में एक व्यवस्थित ब्लूप्रिंट के साथ कार्ययोजना बनाकर राजस्थान में प्राथमिकता से लागू करेंगे और वेस्ट को वेथेथ में कन्वर्ट करने पर हमारा विशेष ध्यान होगा। उन्होंने कहा कि, भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेशभर के निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए सोल्लिड वेस्ट मैनेजमेंट को

जयपुर में हैरिटेज इलाके में 200 करोड़ की लागत से नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी।

जयपुर में हैरिटेज इलाके में 200 करोड़ की लागत से नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिलों के 8 कस्बों तथा 1473 गांवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश के आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़कों से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स संचालित किए जाएंगे, ताकि

वकीलों ने जलाई एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की काँपी



एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में वकीलों में शुक्रवार को हाईकोर्ट के बाहर बिल की होली जलाई।

जयपुर, (का.सं.)। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में वकीलों के खिलाफ कोर्ट परिसर में ही अपराध होने पर ही उन्हें इस कानून का संरक्षण देने और उनके खिलाफ क्लाइंट की ओर से मुकदमा दायर करने की छूट देने के प्रावधान के विरोध में वकीलों ने बिल में संशोधन की मांग की है। इसे लेकर भाजपा से जुड़े कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेक्शन बिल की काँपी जलाई। वहीं संघर्ष समिति ने चेतावनी देते हुए सूचना जारी की है कि यदि संघर्ष समिति की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त यदि किसी अधिवक्ता की ओर से कोई अन्य कार्यक्रम या गतिविधि की गई तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक व दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने बताया कि बिल में संशोधन के लिए संघर्ष

'तय कार्यक्रम के अलावा कुछ किया तो संघर्ष समिति करेगी कार्रवाई'

समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से बिल में संशोधन वाले बिन्दुओं पर वार्ता करने का निर्णय लिया गया। संघर्ष समिति के वकील हाईकोर्ट के गेट नंबर दो से लेकर चार नंबर गेट तक इकट्ठा हो गए। इसका बंद वकील अंबेडकर सफ़िक की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनकी समझाइश कर वापस भेजा। विधि मंत्री से बीसीआर चेयरमैन ने की वार्ता-बिल में जरूरी संशोधनों के लिए बीसीआर चेयरमैन घनश्याम सिंह राठौड़ और एएज्.डी. विभूति भूषण शर्मा ने विधि मंत्री शांति धारीवाल से वार्ता की। मंत्री धारीवाल ने उन्हें और संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को

शनिवार को प्रमुख विधि सचिव के साथ वार्ता करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गत 15 मार्च को विधि मंत्री की ओर से विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल रखा गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि वकील के खिलाफ अदालत परिसर में अपराध होने पर ही प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिल में क्लाइंट को भी वकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।

आम सूचना

दिनांक: 17.03.2023
सर्व सारण को सूचित किया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

आम सूचना

दिनांक: 17.03.2023
सर्व सारण को सूचित किया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

आम सूचना

दिनांक: 17.03.2023
सर्व सारण को सूचित किया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

आम सूचना

दिनांक: 17.03.2023
सर्व सारण को सूचित किया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

आम सूचना

दिनांक: 17.03.2023
सर्व सारण को सूचित किया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

आम सूचना

दिनांक: 17.03.2023
सर्व सारण को सूचित किया जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर
क्रमांक: DHC-403269 दिनांक-17.03.2023

कार्यालय उप आवास आरूक, वृत्त द्वितीय पर्यवेक्षण अधिकारी, अजमेर, जयपुर

e-mail: adicps.blp@rajasthan.gov.in
क्रमांक:-icps/2022-23/2217
दिनांक: 17.03.2023

क्र.सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानत राशि (अमानत लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र विक्रय की समाप्ति तिथि व समय	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	3.70	500/- रुपये	7400/- रुपये	17.03.2023 को प्रातः 9.30 से	22.03.2023 को शाम 5 बजे तक	24.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक	24.03.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक

निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं SPMP Portal पर उपलब्ध हैं।
जिला बाल संरक्षण कार्यालय
जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग